North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

IRJIF IMPACT FACTOR:6.019

ISSN: 2454-2326 Vol. 6, Issue-9 September-2020

Index Copernicus Value: 58.12 DOI NUMBER: 10.5948/2454-2326.2020.00008.0 Citation Index

A Peer Reviewed Refereed Journal

भारत एवं बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन हेतु सरकारी योजनाएं डॉ.

अनामिका कुमारी

विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरानगर दरभंगा।

सार–संक्षेप

भारत के कुल 5,93,732 आबादी गांव में देश के लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्रामीण जनसंख्या में 31.7 प्रतिशत कृषक तथा शेष कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। जिनकी जीवन की पोशाक एवं आय का आधार कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या प्रमुखतः कृषि पर निर्भर है, परंतु वर्तमान में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कम हुई है, जो वर्तमान में 60 प्रतिशत के आसपास है। राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश गिरावट की प्रवृत्ति लिए हुए हैं, तथा आर्थिक विकास के साथ साथ प्रतीत होता है, कि राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान और भी का होता जा रहा है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की स्थिति और अधिक गंभीर है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र के पास भी ऐसी समस्याओं का आर्थिक निदान नहीं है। कृषि क्षेत्र में भू–जोतों के घटते आकार के कारण तथा संगठित उद्योग कुछ विशिष्ट कारणों से जरूरतमंद रोजगार के अवसर सृजित करने में असमर्थ रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की आवश्यकता बिहार में कृषि योग्य भूमि सीमित है, ऐसी दशा में हर ग्रामीण कृषक फसल उत्पादन हेतु कृषि की आधुनिक उन्नत तकनीकी को अपनाना आवश्यक समझते हैं। इन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार में अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बावजूद शासकीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना पड़ता है। बिहार में कृषि उपजाउ की उन्नति के लिए सरकार ने कृषि विकास की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया है।

परिचयः

बिहार में आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिनमें परंपरागत कृषि तकनीकी और तौर–तरीकों से कृषि कार्य किए जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव भी कृषि उत्पादन पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप कृषि से जो उत्पादन होता है, वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता। बिहार में कृषि उत्पादन पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप कृषि से जो उत्पादन होता है, वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं चाहते। साथ ही आधुनिक कृषि के परीकों को भी अपनाना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में दोनो ही तरह के कृषि तकनीकों का संयोजन देखने को मिलता है। कृषि व्यवसाय में हरित क्रांति आधुनिकरण का प्रतीक है। यह परिवर्तन विज्ञान

और प्रौद्योगिकी के फल स्वरूप हो रहे हैं। कृषि व्यवसाय में आधुनिक वैज्ञानिक चीजों का प्रयोग निम्न रूप से किया जा रहा है:

(1)खेत को जोतने और फसल को काटने के लिए ट्रैक्टर तथा अन्य उपकरणों और मशीनों का प्रयोग।

(2) वैज्ञिनिक रासायनिक खाद का प्रयोग करके उपज बढ़ाना।

(3) कपास फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों एवं इल्लियों को कीटनाशकों का छिड़काव कर नष्ट करना।

(4) प्राचीन कृषि उत्पादन पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि पद्धति प्रोत्साहित करना।

बिहार में कृषि उपजो की उन्नति के लिए सरकार ने कृषि विकास की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है:

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिससे गरीब परिवारों की संख्या वाले क्षेत्रों को पहचान करने में मदद मिले एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सहायता मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिला शक्ति एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथिमिकता मिले। इसके अलावा ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में प्रशासनिक सहायता भी प्रदान किया जाता है, जिससे आय की संभावना रहती हैं। इसके अंतर्गत कुशलता प्राप्त करने के बाद वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा ऋण की भी समुचित व्यवस्था की जाती हैं। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा गत 5 वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रूपए के माध्यम से एकत्र किए गए हैं।

(2) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:

भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में जल संसाधन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिससे किसान मछली पालन को अपने व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। मत्स्य में उद्योग की अपार संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया। इस क्षेत्र में सिर्फ मछली पालन उत्पादक तक ही ना रहे। इसके लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है: इसमें उत्पादकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें सुविधाएं एवं आधुनिकरण उपलब्ध कराया जाता है। जिससे की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णत विकसित हो सके एवं उत्पादकों को इसका भरपूर लाथ मिले।

(3) मेगा फूड पार्क योजना:

देश के विभिन्न भागों में 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत ही 'मेगा फूड पार्क' को की स्थापना की गई है। जिससे देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। मेगा फूड पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों उत्पादनकर्ताओं और छोटे–बड़े विभिन्न व्यवसाय को समूह में लाकर उन्हें बाजार से जोड़ना है, जिससे कृषि उत्पाओं की बर्बादी को रोका जा सके एवं कृषि के क्षेत्र में रोजगार अवसर मुहैया कराया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार से प्रभावित युवाओं के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध होगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(4) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:

कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 14वें वित आयोग में 2016–20 तक के लिए 6000 करोड़ रूपए का आवंटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर

खुदरा बिक्री केंद्र तक पूर्ण तह आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना, खाध संस्करण का आधुनिकरण करना, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना। इस योजना से लगभग 20 लाख ग्रामीण को फायदा होगा।

(6) ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान:

देश में गरीबी दूर कर ग्रामीणों को रोजगार और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इससे कृषि कार्यों के अलावा ग्रामीण किसानों एवं युवाओं को अन्य व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जा सके। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों का एकीकरण है। इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ–साथ वित्तीय सहायता देकर भी स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार का आरंभ कर देंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्गों का पलायन भी रूकेगा।

(7) एग्री बिजनेस:

जे कार्यक्रम कृषि और किसान मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से आरंभ किया है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन पर नवीनतम मूल्य संवर्धन करना तथा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ स्वयं का एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करना है। एग्री बिजनेस में किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। बागवानी रेशम उद्योग मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन आ सकता है जिससे स्वरोजगार के अवसर एवं ग्रामीण विकास भी प्रर्याप्त रूप से होगा।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, कि बहुत कृषि आधारित उद्योग है, जिसके माध्यम से मेहनत और प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्रामीण स्तर पर भी रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उस में संपूर्ण जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त करें। उद्योग से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं का पूरा ज्ञान भी आवश्यक है, जिससे उनका आत्मविश्वास एवं आत्म निर्भरता बड़ी। वर्तमान समय में देश में कृषि उत्पादकता एवं खाद सुरक्षा बढाने में कृषि आधारित योजनाओं का महत्वपूर्ण सथान रहा है, जिसमें सरकार ने भी अपनी तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं

ऐसे में स्वरोजगार के क्षेत्र में युवा वर्गों का आकर्षण बढ़ेगा जिससे कृषि क्षेत्रों का पूर्णता विकास होगा एवं ग्रामीण बेरोजगार भी इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

संदर्भ स्त्रोत:

(1) रूद्रदत एवं सुंदरम के (2000) "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड।

(2) यादव जी (2012) भारत में कृषि समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर

(3) गुप्ता वी (2013) "विविधीकरण" साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

(4) गुप्ता वी (2013) "विविधीकरण" साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

(5) दत्ता के (2015) आर्थिक समीक्षा।